RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-05
May-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (सार्क): सफलताएं और चुनौतियाँ

प्रिया कुमारी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार- 846004

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 24 May 2018

Keywords
सार्क, संधि, सफलता, चुनौतियाँ, व्यापार

ABSTRACT

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का कार्यभार संभालने और नई दिल्ली में अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशिया के सभी देशों के नेताओं को आमंत्रित करके एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाने के ठीक 6 माह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काठमांडो में 18 वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दक्षिण एशिया पर ध्यान देने की बात मोदी सरकार बहुत पहले से ही करने लगी थी। प्रधानमंत्री की भूटान और नेपाल यात्रा तथा स्व. विदेशमंत्री सुषमा स्वराज की ढाका, थिम्पू, माले और काठमांडू के दौरों से इस बात को और बल मिला। इस पर यह बात भी ठीक बैठती है कि चूंकि इस क्षेत्र के देशों की नियति एक दूसरे के साथ अंतरंग रूप् से गुंथी हुई है अतः दुनिया भर के दर्जनों नेताओं से मिल कर और कई बड़े बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के बाद श्री मोदी भारत की एशियाई कूटनीति को अभिप्रेरित करने और आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से एकीकृत क्षेत्र के स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए बार-बार पड़ोसी देशों की यात्रा करते हैं।

सार्क की स्थापना कुछ मूल भूत उद्देश्यों को ले कर की गई थी। ये माना गया था कि यदि क्षेत्र के देशों में आपसी सहयोग और मित्रता की भावना सुदृढ़ होगी तो वे परस्पर मिल बैठ कर आपसी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। यही नहीं, यह क्षेत्र महाशक्तियों के आपसी संघर्ष के का क्षेत्र बनने से बचा रह सकेंगा। इसके संस्थापक जियाउर्रमान ने कहा था ‘‘महत्वपूर्ण घटनाओं और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर काफी अंतर हो सकता है, किंतु ये विभिन्नताएं ऐसी खाई बनाने में समर्थ नहीं हैं जिन पर पुल न बनाया जा सके। छुपा हुआ विश्वास आज इसके विकास का स्रोत है।’’

प्रस्तावना:

सार्क, अर्थात विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला आर्थिक और राजनीतिक संगठन। इसके निर्माण का विचार बंगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने रखा था। मालदीव को छोड़ कर बाकी इस संगठन के सभी सदस्य उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर, 1985 को ढाका में हुई, जिसमें सात देश शामिल हुए थे। ये देश थे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। बाद में 3 अप्रेल, 2007 को इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया, इन देश के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के द्वारा सार्क (SAARC) की स्थापना हुयी। इस संगठन का अपना संविधान है. जिसमें 10 धाराएँ हैं। इसके अंतर्गत सार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया है। चूंकि इसकी स्थापना 8 दिसंबर को हुई थी, इसलिए 8 दिसंबर को ‘सार्क दिवस’ मनाया जाता है। 1983 में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक दिल्ली में हुई जिसमें इसकी औपचारिक घोषणा के साथ स्थापना की नींव रखी गई। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोपरेशन का संक्षिप्त रूप है। इसकी स्थापना की बात सबसे पहले 1980 में उठी। अप्रैल 1981 को पहली बार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में इन सातों देशों के सचिवों की बैठक हुई। इसके बाद अगस्त 1983 में दिल्ली में प्रथम बार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। फिर, 7-8 दिसम्बर को हुए शिखर सम्मेलन में एक चार्टर को स्वीकार किया गया और इसी के साथ सार्क का जन्म हुआ। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रत्येक वर्ष अलग-अलग देशों में इसकी बैठक करते हैं। सार्क के विदेश मंत्रियों की परिषद हर साल दो बार बैठक तय हुआ और आवश्यक होने पर अलग से भी परिषद की बैठक हो सकती है।

सार्क के उद्देश्य

सार्क की स्थापना के उद्देश्य सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित किए गए हैं। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. दक्षिण एशिया के देशों की जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।
2. दक्षिण एशियाई देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना।
3. इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास, समाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास की गति को तेज करना।
4. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना।
5. अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आपसी सहयोग को मजबूती देना तथा समस्याओं को समझते हुए एक दूसरे का सहयोग करना।
6. अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाना।
7. सदस्य देशों में आपसी विश्वास बढ़ाना तथा समस्याओं को समझने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

विभिन्न क्षेत्रों में सार्क की सफलताएँ :

सार्क की प्रमुख प्रासंगिकता यही रही कि इसने दक्षिण एशियाई देशों को एक मजबूत मंच प्रदान किया। इसकी उपयोगिता इन अर्थो में भी महत्वपूर्ण रही कि इसके कारण दक्षिण एशिया के सभी देशों को एक साथ बैठ कर अपनी समस्याएं साझा करने का अवसर मिला, यद्यपि जिन उद्देश्यों को ले कर दक्षेस का संगठन हुआ उसमें यह लेशमात्र ही सफल हो पाया।

चूंकि यह वैश्वीकरण का दौर है, विश्व के सारे के सारे देश विन्नि साझा बाजारों, आर्थिक समुदायों अथवा इकॉनोमिक ब्लाक्स के द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था में अपना भविष्य बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। यही कारण है कि ऐसे तमाम संगठन जैसे-आसियान, नाफ्टा, यूरोपीय संघ, इकोसाक, बिम्सटेक, शंघाई सहयोग संगठन, सेकु, कैरीकाम, सेमैक, ईएसी जैसे विभिन्न साझा बाजार पूरी दुनिया में अपनी उपलब्धि दर्ज करा चुके हैं।

उसी प्रकार दक्षिण दक्षिण एशियाई के देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1995 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) की संधि हो चुकी है, परंतु दक्षिण एशियाई देशों के बीच सीमा विवाद, राजनीतिक विवाद एवं सामरिक रणनीति की छाया रहने के कारण सामूहिक आर्थिक विकास पर परस्पर व्यापार के मोर्चे पर आशातीत सफलता नहीं मिल सकी है।

भविष्य में भी ऐसे मंचों की संभावनाएं बनी रहेंगी। करीब ढाई दशक पहले एक्षिण एशिया के देशो ने भी एक ऐसे ही मंच सार्क की स्थापना की। इसका उद्देश्य विश्य अर्थव्यवस्था में अपना भविष्य सुनिश्चित करने की कोशिश करना था। लेकिन दक्षेस के देश इसमें सफल नहीं हो पाए।

हालांकि कृषि के क्षेत्र में सार्क ने कुछ उम्मीद जगाई थी। हरित क्रांति के कारण जहां भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा, वहीं पाकिस्तान कॉटन के लिए अग्रणी देश माना जाने लगा। बंगलादेश चावल के लिए और मालद्वीप मत्स्य उत्पादन के लिए। श्रीलंका में चाय और नारियल का उत्पादन बढ़ा वहीं नेपाल और भूटान मक्के का बहुतायत में उत्पादन करते हैं। इन उत्पादों का लाभ भी ये सारे देष आपस में एक दूसरे का सहयोग करके उठाते हैं। यही नहीं, कृषि, में निवेश हेतु बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जिसमें उर्वरक, मृदा और जल प्रबंधन, फसल परिवर्तन आदि आते हैं। दक्षिण एशिया एक ही प्रकार की मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। अतः यदि राष्ट्र चाहें तो कृषि से संबंधित अनुसंधान, मृदा अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के द्वारा क्षेत्र की कृषि से जुड़े व्यापार एवं उद्योग में भारी उन्नति कर सकते हैं।

विवनीकरण के अंतर्गत बांग्लादेश और पाकिस्तान निर्वनीकरण से सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। नेपाल में ईंधन की पूर्ति के लिए जंगली लकड़ियों पर निर्भरता के कारण वनों पर दबाव बढ़ रहा है। इसके सिवा सड़कों के निर्माण से भी जंगल नष्ट हो रहे हैं। यह एक दुःखद स्थिति हे। इस प्रकार की उदासीनता और विफलता के कारण ही दक्षेस के बारे में कहा जाने लगा है कि ‘‘17 शिखर और उपलब्धि सिफर’’ इसका सीध सा अर्थ है कि दक्षेस अपनी मैकेनिज्म को परिवर्तित करने में नाकाम रहा। यही कारण है कि दक्षिण एशिया संसार के सबसे अधिक गरीबों का निवास स्थान माना जाने लगा। युवाओं और महिलाओं में रोजगार और आत्मनिर्भरता की दर बहुत ही कम है। कुपोषित बच्चों की संख्या 25 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। प्रायः महिलाओं का प्रसव घर में ही कराया जाता है। उनके स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े भी काफी सोचनीय हैं। यही नहीं, इकोवास जैसे संगठन जिसमें दुनिया के सबसे पिछड़े देश आते हैं, वहां के बराबर दक्षिण एशिया की प्रतिव्यक्ति आय है।

उक्त कारणों के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि इस संगठन में कुछ ऐसा है जो विशेष है। पड़ोसी देश चीन, म्यंमार और इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि रूस जैसे देश भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। चीन तो इसमें शामिल होने की इच्छा काफी पहले व्यक्त कर चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसकी सदस्यता का समर्थन भी करते रहे हैं। जबकि भारत विरोध करता रहा है। फिर भी 2005 के दौरान भारत इसे जापान के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए सहमत हुआ। इंडोनेशिया और म्यांमार की भी यही स्थिति है। वही ईरान इसमें सम्मिलित होने के लिए यह तर्क देता है कि पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ सशक्त संस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संबंध हैं और दक्षेस से जुड़ कर वह पूरब तथा पश्चिम के साथ इसे जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। दूसरी तरफ रूस भी इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होना चाहता है। स्पष्ट है अगर इतने देश इस संगठन में शामिल होने के लिए लालायित हैं तो अवश्य इसमें वे अपना कोई लाभ अथवा अवसर देख रहे हैं।

दक्षेस की सफलता की संभावनाएँ

वास्तव में यदि इतने देश सार्क के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो इसकी वजह इसके पीछे छुपे हुए तमाम लाभ हैं। ये लाभ राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक सभी प्रकार के हैं। पहला लाभ तो यही है कि 1.6 बिलियन से अधिक लोगों का बाजार और प्रकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के साथ दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था बहुत ही संभावनापूर्ण है। इसी तरह कई रणनीतिक समीकरणों के समाधान भी निहित हैं। अफगानिस्तान, हिंद महासागर रिम, खाड़ी क्षेत्र, इराक से अमेरिकी सेना की विदाई के बाद मध्य-पूर्व की स्थिति और एशिया प्रशांत में जो नए राजनीतिक समीकरण निर्मित हो रहे हैं वे दक्षिण एशिया को महत्वपूर्ण बना रहे हैं। दक्षिण एशिया के लिए यह अनिवार्य है कि वह पहले आर्थिक रूप से समृद्ध बने जिसकी संभावनाएं अपार हैं। इसी प्रकार पर्यटन की बात करें तो विशेषकर अफगानिस्तान और नेपाल को इससे काफी लाभ पहुंच सकता है। गैर- परंपरागत क्षेत्रों में ऊर्जा और बिजली के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग व्यापार संबंधों को विकसित करने की दिशा में बेहतर ट्रैक साबित हो सकता है। इस क्षेत्र में भूटान और भारत का उदाहरण लिया जा सकता है। हाईड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर के क्षेत्र में ऐसी ही संभावनाएं बांग्लादेश और नेपाल में निहित हैं। दक्षिण एशिया में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को आपस में जोड़ने से ऊर्जा कीमतों में कमी भी आएगी और दक्षेस देश मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में सशक्त प्रतियोगी बन कर उभरेंगे। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, और भारत इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे।

सार्क के सामने चुनौतियां

अर्थशास्त्री जिल जेम्स कहते हैं कि''सार्क देशों के कुल व्यापार का बस पांच प्रतिशत हिस्सा ही ऐसा है जहां इनमें आपसी व्यापार होता है।'' निःसंदेह, यही सबसे बड़ी चुनौती है दक्षेस के सामने। सार्क के प्रतिनिधियों ने आर्थिक वृद्धि का जो खाका तैयार किया है उसे अमली जामा पहनाए जाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जिल जेम्स आगे कहते हैं कि ''यह एक अच्छी शुरूआत अवश्य है मगर मुक्त व्यापार क्षेत्र को हासिल करना एक बड़ी चुनौती है।"

पहली सबसे बड़ी चुनौती है मजदूरी का अंतर। मुक्त व्यापार को लेकर सबसे बड़ी चिंता है, भारत जैसे बड़े देशों को जिन्हें लगता है कि बाजार खुलने से सार्क के गरीब देश अपने सस्ते सामान लेकर उनके बाजारों में न चले आएं। गरीब देशों में मजदूरी की नीची दर के कारण सामानों की कीमतें भी कम होती हैं। ऐसी हालत में सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार का भविष्य काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि भारत का रवैया क्या रहता है।

दूसरी समस्या यह है कि सार्क देश आपस में बहुत अधिक व्यापार नहीं करते। कपड़े, चाय, चीनी जैसे उत्पादों का अधिकतर सदस्य देश निर्यात करते हैं। जिल जेम्स का मानना है कि सार्क देश के कुल पांच प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जहां इसमें आपसी व्यापार होता है। इसी प्रकार सार्क देशों की योजनाए हैं कि करों में कटौती की जाए और अलग-अलग देशों के अलग-अलग उद्योगों पर विशेष ध्यान दे कर समस्याओं का निदान किया जाए। यही नहीं, सार्क देशों में राजनीतिक परंपरा भी कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर रही है। यही कारण है कि यह संगठन अभी तक कुछ विशेष उपलब्धि नहीं हासिल कर पाया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधारों को लेकर था जिसमें उपलब्धि न के बराबर रही। सफलता के नाम पर एक सार्क यूनिवर्सिटी को ही देखा जा सकता है। व्यापारिक लेनदेन की प्रक्रिया में भी कई तरह की अड़चनें हैं। इनमें राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी बहुत अभाव है।

सार्क देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास को लेकर है। दूसरी चुनौती है आपसी संपर्कों को लेकर। सार्क देशों के बीच लोगों के अवागमन, सामान-उत्पाद की लेन देन मे आती बाधाएं भी चुनौतियां ही हैं। सुरक्षा को लेकर भी इनमें आपस में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सुरक्षा की भी चुनौती है। आपसी व्यापार के लिए सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। वीजा मिलने में काफी समय लगना भी एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से तात्कालिक व्यापार के अवसर हाथ से जाते रहते हैं। अतः सार्क देशों को उक्त सभी चुनौतियों का निबटारा करना होगा जो बहुत ही जरूरी है।

सार्क की वर्तमान स्थिति

सार्क की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण इसके अंदर का अंतर्द्वंद्व है। सार्क सम्मेलन 2014 काठमांडू में हुआ था। 19वां सार्क सम्मेलन 2016 पाकिस्तान में होना था, जिसका भारत समेत अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश ने बहिष्कार किया और वह सम्मेलन रद्द करना पड़ा। इसका कारण बताया गया 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के शिविर पर आतंकी हमला। भारत ने वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सम्मेलन में हिस्सा लेने में अपनी असमर्थता जताई। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि ''दक्षेस की स्थापना एकीकृत और जुड़े हुए दक्षिण एशिया निर्माण के लिए की गई थी जिसका उद्देश्य क्षेत्र में सभी देशों के विकास और प्रगति को बढ़ावा देना था।'' इसके बाद लगातार असहमतियों की स्थिति बनी हुई है। 20वां सार्क सम्मेलन फिर से इस्लामाबाद में आयोजित करने की बात चली लेकिन फिर आपसी मतभेदों के कारण यह तय हुआ कि 20वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं कि सार्क की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है।

निष्कर्ष

वास्तव में सार्क की शक्ति इसकी क्षमता और विकास इसके सदस्य देशों पर निर्भर करता है। आपसी सहयोग और मित्रवत संबंध इसके विकास और स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां प्रायः सार्क के उद्देश्यों तथा कार्यशैली में बाधा डालने का प्रयास करती रहती हैं इसलिए उनसे सावधान रहने तथा उनको मुंहतोड़ जवाब देने की भी आवश्यकता है। सार्क को पूर्वाग्रह, संदेह, घृणा और भेदभाव जैसी मानसिकताओं से बचना होगा। वहीं तकनीकी सहयोग, व्यापार का सरलीकरण, आदि अर्थिक और राजनीतिक विकास में सहयोग कर सकते हैं जो दक्षेस की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाएगा। संस्कृति, धर्म, सामाजिक और नस्लीय समानता आपसी भाईचारे के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। किसी भी प्रकार की असहिष्णुता और सामाजिक समस्या सकारात्मक विकास को बाधित कर सकती है। ये सार्क के देशों पर निर्भर करता है कि वे उसे सफल देखना चाहते हैं अथवा विफल।

संदर्भ सूची:

1. फड़िया, बी. एल. (2014), अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत और सार्क,आगरा: साहित्य भवन पब्लिकेशन
2. आई. डी. एस. (अक्तूबर, 1987), साउथ एशियन न्यूज रिव्यू
3. सिंह, हरिकिशोर, (31अगस्त,1989), दक्षेस की दयनीयताः संदेह, शंका और अविश्वास का माहौल, दिनमान
4. सैनी, बी. (2018), सार्क: चैलेन्ज एंड प्रोस्पेक्टस, हिबरो स्क्रिब पब्लिकेशन
5. सुधाकर, ई. (1994), सार्क: ओरिजिन, ग्रोथ एंड फ्यूचर, दिल्ली: ज्ञान पब्लिशिंग हाउस
6. गोपाल, ओ. पी. (2018), इंडिया एंड सार्क इंगेजमेंट, दिल्ली: ज्ञान बुक्स
7. Mohan, C. Raja. (2015), Modi's world India: Harper Colins Publishers.
8. विस्वाल, तपन. (2016), अंतरराष्ट्रीय संबंध. हैदराबाद: ओरिएंट ब्लैकस्वान

9. सीकरी, राजीव. (2017), भारत की विदेश नीति. लंदन: सेज भाषा
10. गांगुली, सुमित.(संपा.). (2018), भारत की विदेश नीति पुनरावलोकन एवं संभावनाएं. भारत :आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
11. योजना, (जुलाई, 2015), अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नए आयाम
12. वल्ड फोकस, (मार्च, 2015), विशेषांक भारत की नई विदेश नीति, भाग-2
13. hhtp://www.pravakta.com
14. satyagrah.scroll.in

RRIJM 2015, All Rights Reserved